

CATV NETWORK (AMENDMENT) RULES, 2021 GUIDELINES

*CATV Network (Amendment) Rules, 2021
provides Statutory Mechanism for Grievances
Redressal of Television Content*

STATUTORY MECHANISM FOR GRIEVANCES REDRESSAL OF TELEVISION CONTENT

The Central Government issued a notification on 17th June 2021 amending the Cable Television Network Rules, 1994 thereby providing a statutory mechanism for redressal of grievances/complaints of citizens relating to content broadcast by television channels in accordance with the provisions of the Cable Television Network Act, 1995.

At present, there is an institutional mechanism by way of an Inter-Ministerial Committee to address grievances of citizens relating to violation of the Programme/Advertising Codes under the Rules. Similarly, various broadcasters have also developed their internal self-regulatory mechanism for addressing grievances. However, a need was felt to lay down a statutory mechanism for strengthening the grievance redressal structure. Some broadcasters had also requested for giving legal recognition to their associations/bodies. The Hon'ble Supreme Court in its order in WP(C) No.387 of 2000 in the matter of "Common Cause Vs Union of India & Others" while expressing satisfaction over the existing mechanism of grievance redressal set up by the Central Government, had advised to frame appropriate rules to formalize the complaint redressal mechanism.

In the aforementioned background, the Cable Television Network Rules have been amended to provide for this statutory mechanism, which would be transparent



सीएटीवी नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 दिशानिर्देश

*सीएटीवी नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 टेलीविजन
कार्यक्रम की शिकायत निवारण के लिए
वैधानिक तंत्र प्रदान करता है*

टेलीविजन सामग्री के शिकायत निवारण के लिए वैधानिक तंत्र

केंद्र सरकार ने 17 जून 2021 को केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन करते हुए एक अधिसूचना जारी की, जिससे केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1995 के प्रावधानों के अनुसार टेलीविजन चैनलों द्वारा प्रसारित सामग्री से संबंधित नागरिकों की शिकायतों/शिकायतों के निवारण के लिए एक वैधानिक तंत्र प्रदान किया गया।

वर्तमान में नियमों के तहत कार्यक्रम/विज्ञापन संहिताओं के उल्लंघन से संबंधित नागरिकों की शिकायतों को दूर करने के लिए एक अंतर मंत्रालयी समिति के माध्यम से एक संस्थागत तंत्र है। इसी तरह विभिन्न प्रसारकों ने भी शिकायतों के समाधान के लिए अपने आंतरिक स्व-नियामक तंत्र का विकास किया है। तथापि शिकायत निवारण ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए एक सांविधिक तंत्र बनाने की आवश्यकता महसूस की

गयी। कुछ प्रसारकों ने अपने संघों/निकायों को कानूनी मान्यता देने का भी अनुरोध किया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2000 के डब्ल्यूपी (सी) संख्या 387 में 'सामान्य कारण बनाम भारत संघ और अन्य' के मामले में अपने आदेश में केंद्र सरकार द्वारा स्थापित शिकायत निवारण के मौजूदा तंत्र पर संतोष व्यक्त करते हुए शिकायत निवारण तंत्र को औपचारिक रूप देने के लिए उचित नियम बनाने की सलाह दी थी।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में इस वैधानिक तंत्र को प्रदान करने के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमों में संशोधन किया गया है, जो पारदर्शी

and benefit the citizens. At the same time, self-regulating bodies of broadcasters would be registered with the Central Government.

At present there are over 900 television channels which have been granted permission by the Ministry of Information and Broadcasting all of which are required to comply with the Programme and Advertising Code laid down under the Cable Television Networks Rules. The above notification is significant as it paves the way for a strong institutional system for redressing grievances while placing accountability and responsibility on the broadcasters and their self-regulating bodies.

In exercise of the powers conferred by section 22 of the Cable Television Networks (Regulation), Act, 1995 (7 of 1995), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cable Television Networks Rules, 1994, namely:

SHORT TITLE AND COMMENCEMENT

- (1) These rules may be called the Cable Television Networks (Amendment) Rules, 2021.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

In rule 6 of the Cable Television Networks Rules, 1994 (hereinafter referred to as the said rules), after sub-rule (6), the following sub-rule shall be inserted, namely:

“(7) where the Central Government is satisfied that the programme of any channel is not in conformity with the Programme Code, it may, after giving an opportunity of hearing to the cable operator, and by an order in writing, prohibit the transmission or re-transmission of any such channel or programme in accordance with the provisions of section 20 of the Act.”

In rule 7 of the said rules, after sub-rule (11), the following subrule shall be inserted, namely:

“(12) where the Central Government is satisfied that the advertisement of any channel is not in conformity with the Advertising Code, it may, after giving an opportunity of hearing to the cable operator, and by an order in writing, prohibit the transmission or re-transmission of any such channel or programme in accordance with the provisions of section 20 of the Act.”

होगा और नागरिकों को लाभांशित करेगा। वहीं, प्रसारकों के स्व-नियामक निकाय केंद्र सरकार के पास पंजीकृत होंगे।

वर्तमान में 900 से अधिक टेलीविजन चैनल हैं जिन्हें सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा अनुमति दी गयी है जिनमें से सभी को केवल टेलीविजन नेटवर्क नियमों के तहत निर्धारित कार्यक्रम और विज्ञापन कोड का पालन करना आवश्यक है। उपरोक्त अधिसूचना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शिकायतों के निवारण के लिए एक मजबूत संस्थागत प्रणाली का मार्ग प्रशस्त करती है जबकि जवाबदेही और जिम्मेदारी प्रसारकों और उनके स्व-नियामक निकाय को।



सत्यमेव जयते
Ministry of Information & Broadcasting
Government of India

जी.एस.आर.416 (ई)- केवल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम), अधिसूचना 1995 (1995 का 7) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार केवल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

- (1) इन नियमों को केवल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम 2021 कहा जा सकता है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगा।

केवल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 (जिसे इसमें इसके बाद उक्त नियम कहा गया है) के नियम 6 में, उप नियम (6) के बाद, निम्नलिखित उप-नियम डाला जायेगा, अर्थात्

“(7) जहां केंद्र सरकार संतुष्ट है कि किसी भी चैनल का कार्यक्रम कार्यक्रम संहिता के अनुरूप नहीं है, वह केवल ऑपरेटरों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, और लिखित आदेश द्वारा प्रतिबंधित कर सकती है, अधिनियम की धारा 20 के प्रावधानों के अनुसार ऐसे किसी भी चैनल या कार्यक्रम के प्रसारण या पुन-प्रसारण को प्रतिबंधित करे।

उक्त नियमों के नियम 7 में उप-नियम (11) के बाद निम्नलिखित उप-नियम शामिल किया जायेगा, अर्थात्

“(12) जहां केंद्र सरकार संतुष्ट है कि किसी भी चैनल का विज्ञापन विज्ञापन संहिता के अनुरूप नहीं है, वह केवल ऑपरेटरों को सुनवाई का अवसर देने के बाद और लिखित में एक आदेश के द्वारा या अधिनियम की धारा 20 के प्रावधानों के ऐसे किसी भी चैनल या कार्यक्रम के पुन-प्रसारण को प्रतिबंधित कर सकती है।

CATV GUIDELINES

In the said rules, after rule 14, the following rules shall be inserted, namely:

COMPLAINT REDRESSAL STRUCTURE

To ensure observance and adherence to the Programme Code and the Advertising Code by the broadcaster and to address the grievance or complaint, if any, relating thereto, there shall be a three-level structure as under:

LEVEL I	A self-regulation by broadcasters;
LEVEL II	Self-regulation by the self regulating bodies of the broadcasters; and
LEVEL III	Oversight mechanism by the Central Government

FILING AND PROCESSING OF GRIEVANCE OR COMPLAINT

- (1) Any person aggrieved by the content of a programme of a channel as being not in conformity with the Programme Code or the Advertising Code may file his complaint in writing to the broadcaster:

Provided that where such complaint relates to Advertising Code laid down by the Advertising Standards Council of India, such complaint may be addressed to the said Council and that Council shall deal with such complaint in accordance with the procedure laid down by it :

Provided further that Advertising Standards Council of India shall take a decision on the complaint within sixty days of its receipt, and communicate the same to the broadcaster and the complainant.

- (2) The broadcaster shall, within twenty-four hours of complaint being filed, generate and issue an acknowledgement to the complainant for his information and record.
- (3) Every complaint shall be dealt with in the following manner, namely: -
 - (a) the broadcaster shall dispose of the complaint and inform the complainant of its decision within fifteen days of receipt of such complaint;
 - (b) if the decision of the broadcaster is not communicated to the complainant within the stipulated period of fifteen days, or if the complainant is not satisfied with the decision of the broadcaster, he may prefer an appeal to the

उक्त नियमों में नियम 14 के बाद निम्नलिखित नियम जोड़े जायेंगे, अर्थात् :

शिकायत निवारण संरचना

प्रसारक द्वारा कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता का पालन और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए और शिकायत या शिकायत, यदि कोई हो, को संबोधित करने के लिए एक तीन-स्तरीय संरचना निम्नानुसार होगी:-

लेवल 1	प्रसारकों द्वारा स्व-विनियमन
लेवल 2	प्रसारकों के स्व-विनियमन निकायों द्वारा स्व-विनियमन, और
लेवल 3	केंद्र सरकार द्वारा निगरानी तंत्र

शिकायत या शिकायत दर्ज करना और उस पर कार्रवाई करना

- (1) कोई भी व्यक्ति किसी चैनल के कार्यक्रम की सामग्री से व्यथित है, क्योंकि वह कार्यक्रम कोड या विज्ञापन कोड के अनुरूप नहीं है, वह प्रसारकों को लिखित रूप में अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है:
वशर्ते कि जहां ऐसी शिकायत भारतीय विज्ञापन मानक परिषद द्वारा निर्धारित विज्ञापन संहिता से संबंधित है, ऐसी शिकायत को उक्त परिषद को संबोधित किया जा सकता है और वह परिषद ऐसी शिकायत से उसके द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निपटेगी:
वशर्ते यह भी कि एडवरटाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया शिकायत प्राप्त होने के साठ दिनों के भीतर निर्णय लेगी और प्रसारकों व शिकायतकर्ताओं को इसकी सूचना देगी।
- (2) प्रसारक, शिकायत दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर, शिकायतकर्ता को उसकी जानकारी और रिकॉर्ड के लिए एक रसीद तैयार करेगा और जारी करेगा।
- (3) प्रत्येक शिकायत को निम्नलिखित तरीकों से निपटाया जायेगा, अर्थात्
 - (ए) प्रसारक शिकायत का निपटारा करेगा और शिकायतकर्ताओं को इस तरह की शिकायत प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अपने निर्णय के बारे में सूचित करेगा,
 - (बी) यदि 15 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर शिकायतकर्ता को प्रसारक के निर्णय की सूचना नहीं दी जाती है या यदि शिकायतकर्ता प्रसारक के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो

self-regulating body of which such broadcaster is a member, within fifteen days therefrom;

- (c) the self-regulating body shall dispose of the appeal within sixty days of receipt of appeal and convey its decision in the form of a guidance or advisory to the broadcaster, and inform the complainant of such decision within a period of fifteen days;
- (d) where the complainant is not satisfied with the decision of the self-regulating body, he may, within fifteen days of such decision, prefer an appeal to the Central Government for its consideration under the Oversight Mechanism referred to in rule 19.

SELF-REGULATION BY BROADCASTER

- (1) A broadcaster shall
 - (i) establish a grievance or complaint redressal mechanism and appoint an officer to deal with the complaints received by it;
 - (ii) display the contact details related to its grievance redressal mechanism, the name and contact details of its Grievance officer at an appropriate place on its website or in interface, as the case may be;
 - (iii) ensure that such Officer takes a decision on every grievance or complaint received by it within fifteen days and communicate the same to the complainant within the stipulated time;
 - (iv) be a member of a self-regulating body and abide by its terms and conditions.
- (2) The Officer referred to in sub-rule (1) shall –
 - (i) be the contact point for receiving any grievance or complaint relating to Programme Code and Advertising Code;
 - (ii) act as the nodal point for interaction with the complainant, the self-regulating body and the Central Government
- (3) The broadcaster shall comply with every advisory, guidance, order or direction issued under this rule by the self-regulating body or by the Central Government, as the case may be.



वह स्व-विनियमन निकाय को अपील कर सकता है, ऐसे प्रसारक जिसके 15 दिनों के भीतर उसके सदस्य होते हैं।

- (सी) स्व-विनियमन निकाय अपील की प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर अपील का निपटान करेगा और प्रसारक को मार्गदर्शन या सलाह के रूप में अपने निर्णय से अवगत करायेगा और शिकायतकर्ता को इस तरह के निर्णय के बारे में 15 दिनों की अवधि के भीतर सूचित करेगा
- (डी) जहां शिकायतकर्ता स्व-विनियमन निकाय के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, वह इस तरह के निर्णय के 15 दिनों के भीतर नियम 19 में संदर्भित निगरानी तंत्र के तहत केंद्र सरकार के विचार के लिए अपील कर सकता है।

प्रसारक द्वारा स्व-नियमन

- (1) एक प्रसारक
 - (i) एक शिकायत या शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करेगा और उसे प्राप्त शिकायतों से निपटने के लिए एक अधिकारी नियुक्त करेगा
 - (ii) अपनी शिकायत निवारण तंत्र से संबंधित संपर्क वितरण, इसके शिकायत अधिकारी का नाम और संपर्क विवरण अपनी वेबसाइट या इंटरफेस पर उपयुक्त स्थान पर, जैसा भी मामला हो, प्रदर्शित करेगा।
 - (iii) सुनिश्चित करें कि ऐसा अधिकारी पंद्रह दिनों के भीतर प्राप्त प्रत्येक शिकायत या शिकायत पर निर्णय लेता है और निर्धारित समय के भीतर शिकायतकर्ता को इसकी सूचना देता है।
 - (iv) एक स्व-विनियमन निकाय के सदस्य बनें और इसके नियमों व शर्तों का पालन करें।
- (2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट अधिकारी-
 - (i) किसी भी शिकायत को प्राप्त करने के लिए संपर्क बिंदु बने या प्रोग्राम कोड और विज्ञापन कोड से संबंधित शिकायत
 - (ii) शिकायतकर्ता, स्व-विनियमन निकाय और केंद्र सरकार के साथ बातचीत के लिए नोडल बिंदु के रूप में कार्य करना।
- (3) प्रसारक इस नियम के तहत स्व-विनियमन निकाय या केंद्र सरकार द्वारा जारी प्रत्येक सलाह, मार्गदर्शन, आदेश या निर्देश का पालन करेगा, जैसा भी मामला हो।

CATV GUIDELINES

SELF-REGULATION BY THE SELF-REGULATING BODY OF BROADCASTERS

- (1) There may be one or more self-regulatory body of broadcasters, being an independent body constituted by the broadcasters or its association:

Provided that every such self-regulating body shall be constituted by a minimum of forty broadcasters

- (2) Every self-regulating body referred to in sub-rule (1) shall be headed by a retired judge of the Supreme Court or of a High Court or an independent eminent person from the field of media, broadcasting, entertainment, child rights, human rights or such other relevant fields, and shall have other members, preferably not exceeding six, being independent experts in the field of media, broadcasting, entertainment, child rights, human rights and such other relevant fields.

- (3) The self-regulating body shall, after its constitution in accordance with sub-rule (2), register itself with the Central Government within a period of thirty days from the date of publication of these rules, or within thirty days from the date of its constitution, whichever is earlier:

Provided that before granting registration to the selfregulating body, the Central Government shall

प्रसारकों के स्व-विनियमन निकाय द्वारा स्व-विनियमन

- (1) प्रसारकों का एक या एक से अधिक स्व-विनियामक निकाय हो सकता है जो प्रसारकों या उसके संघ द्वारा गठित एक स्वतंत्र निकाय है:

बशर्ते कि ऐसे प्रत्येक स्व-विनियमन निकाय का गठन न्यूनतम चालीस प्रसारकों द्वारा किया जायेगा।

- (2) उप-नियम में संदर्भित प्रत्येक स्व-विनियमन निकाय (1) सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या मीडिया, प्रसारण, मनोरंजन, बाल अधिकार, मानवाधिकार या ऐसे अन्य संबंधित क्षेत्रों के एक स्वतंत्र प्रतिष्ठित व्यक्ति की अध्यक्षता में होगा, इसके अलावा अन्य सदस्य होंगे, अधिमानतः छह से अधिक नहीं, मीडिया, प्रसारण, मनोरंजन, बाल अधिकार, मानवाधिकार और ऐसे अन्य प्रासंगिक क्षेत्रों के क्षेत्र में स्वतंत्र विशेषज्ञ होने के नाते।

- (3) स्व-विनियमन निकाय, उप-नियम (2) के अनुसार अपने गठन के बाद इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर या तीस के भीतर केंद्र सरकार के साथ खुद को पंजीकृत करेगा। इसके गठन की तारीख से, जो भी पहले हो:

बशर्ते कि स्व-विनियमन को पंजीकरण प्रदान करने से पहले,

Cut This Coupon & Send It To Us.



Free INDUSTRY UPDATES & BREAKING NEWS!



Please Save Mob.: +91-70218 50198 in Your Phone Contact List For WhatsApp Updates

Yes, Please Send Me Information & News Related To Indian Cable TV & Broadband By WhatsApp, E-Mail & SMS to The Following:

Mobile No.

Email Add.

Name:

Signature



Cut This Coupon & Send It To Us At: **SATELLITE & CABLE TV Magazine**

Address: 312/313, A Wing, 3rd Floor, Dynasty Business Park, Andheri Kurla Road, Andheri (E), Mumbai - 400 059
Tel.: +91-22-6516 5320 Mob.: +91-70218 50198 Email: sales@scatmag.com / scat.sales@nm-india.com

CATV GUIDELINES

satisfy itself that the self-regulating body has been constituted in accordance with sub-rule (2) and has agreed to perform the functions specified in sub-rules (4) and (5).

(4) The self-regulating body shall perform the following functions, namely

- (i) oversee and ensure the alignment and adherence by the broadcaster to the Programme Code and the Advertising Code;
- (ii) provide guidance to the broadcaster on various aspects of the Programme Code and the Advertising Code;
- (iii) dispose of grievances which have not been disposed of by the broadcaster within the specified period of fifteen days;
- (iv) hear appeals filed by the complainant against the decision of the broadcaster;
- (v) issue such guidance or advisories to a broadcaster, including those specified in sub-rule (5), for ensuring compliance to the Programme Code and the Advertising Code.



(5) A self-regulating body while disposing complaint or an appeal referred to in sub-rule (4) may issue the following guidance or advisories to the broadcaster, namely: -

- (i) advisory, warning, censure, admonish or reprimand; or
- (ii) an apology to be telecast by the broadcaster; or
- (iii) include a warning card or a disclaimer; or
- (iv) in case of any content where it is satisfied that there is a need for taking action to delete or modify content, refer it to the Central Government for the consideration of the oversight mechanism referred to in rule 19 for appropriate action.

(6) where the self-regulating body is of the opinion that there is no violation of the Programme Code or the Advertising Code, it shall convey such decision to the complainant and the broadcaster.

(7) Where the broadcaster fails to comply with the guidance or advisory of the self-regulating body within the time specified in such guidance or

केंद्र सरकार स्वयं को संतुष्ट करेगी कि स्व-विनियमन निकाय का गठन उप-नियम (2) के अनुसार किया गया है और उप नियम (4) व (5) में निर्दिष्ट कार्यों को करने के लिए सहमत है।

(4) स्व-विनियमन निकाय निम्नलिखित कार्य करेगा, अर्थात्

- (i) कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता के प्रसारक द्वारा सख्ख और अनुपालन की देखरेख और सुनिश्चित करना
- (ii) कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता के विभिन्न पहलुओं पर प्रसारक को मार्गदर्शन प्रदान करना
- (iii) पंद्रह दिनों की निर्दिष्ट अवधि के भीतर उन शिकायतों का निपटान जो प्रसारक द्वारा नहीं किया गया है,

(iv) प्रसारक के निर्णय के विरुद्ध शिकायतकर्ता द्वारा दायर अपीलों की सुनवाई करना

(v) कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उप-नियम (5) में निर्दिष्ट लोगों सहित किसी प्रसारक को इस तरह के मार्गदर्शन या सलाह जारी करना।

(5) एक स्व-विनियमन निकाय शिकायत और उप-नियम (4) में निर्दिष्ट अपील का निपटान करते समय प्रसारक को निम्नलिखित मार्गदर्शन या सलाह जारी कर सकता है, अर्थात्

- (i) सलाह, चेतावनी, निंदा, निंदा या फटकार या
- (ii) प्रसारक द्वारा प्रसारित की जाने वाली माफी या
- (iii) चेतावनी कार्ड या अस्वीकरण शामिल करें, या
- (iv) किसी भी सामग्री के मामले में जहां यह संतुष्ट है कि सामग्री को हटाने या संशोधित करने के लिए कार्रवाई करने की आवश्यकता है, उचित कार्रवाई के लिए नियम 19 में संदर्भित निगरानी तंत्र के विचार के लिए इसे केंद्र सरकार को संदर्भित करे।

(6) जहां स्व-विनियमन निकाय की राय है कि कार्यक्रम संहिता या विज्ञापन संहिता का कोई उल्लंघन नहीं है, वह शिकायतकर्ता और प्रसारक को इस तरह के निर्णय से अवगत करायेगा।

(7) जहां प्रसारक इस तरह के मार्गदर्शन या सलाह में निर्दिष्ट समय के भीतर स्व-विनियमन निकाय के मार्गदर्शन या सलाह का पालन करने

CATV GUIDELINES

advisory, the self-regulating body shall refer the matter to the Oversight Mechanism referred to in rule 19 within fifteen days of expiry of the stipulated period.

OVERSIGHT MECHANISM

The Central Government shall coordinate and facilitate the adherence to the Programme Code and the Advertising Code by the broadcaster, develop an Oversight Mechanism, and perform the following functions, namely: -

- (i) publish a charter for self-regulating bodies, including Codes of Practices for such bodies;
- (ii) establish an Inter-Departmental Committee for hearing grievances or complaints;
- (iii) refer to the Inter-Departmental Committee grievance or complaints arising out of the decision of the self-regulating body under rule 17, or if no decision has been taken by the self-regulating body within the stipulated time, or on receipt of such other complaints or references relating to violation of Programme Code or Advertising Code as it may consider necessary;
- (iv) issue appropriate guidance and advisories to broadcasters;
- (v) issue appropriate orders and directions to broadcasters for maintenance and adherence to the Programme Code and the Advertising Code;
- (vi) take action for non-compliance of its orders or directions and that of the self-regulating body.

INTER-DEPARTMENTAL COMMITTEE

- (1) The Central Government shall constitute an Inter-Departmental Committee, chaired by the Additional Secretary in the Ministry of Information and Broadcasting, and consisting of representatives from the Ministry of Women and Child Development, Ministry of Home Affairs, Ministry of Electronics and Information Technology, Ministry of External Affairs, Ministry of Defence, and representatives of such other Ministries and Organisations, including experts, as the Central Government may decide
- (2) The Inter-Departmental Committee shall devise its own procedure for hearing grievances or complaints.
- (3) The Committee shall meet periodically and hear complaints regarding violation or contravention of the Programme Code and the Advertising Code that may –

में विफल रहता है, स्व-विनियमन निकाय निर्धारित अवधि की समाप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर मामले को नियम 19 में निर्दिष्ट निरीक्षण तंत्र को संदर्भित करेगा।

निरीक्षण तंत्र

केंद्र सरकार प्रसारक द्वारा कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता के अनुपालन में समन्वय और सुविधा प्रदान करेगी, एक निगरानी तंत्र विकसित करेगी और निम्नलिखित कार्य करेगी, अर्थात्:

- (i) स्व-विनियमन निकायों के लिए एक चार्टर प्रकाशित करना, जिसमें ऐसे निकायों के लिए आचार संहिता शामिल है
- (ii) शिकायतों या शिकायतों की सुनवाई के लिए एक अंतर-विभागीय समिति की स्थापना करना
- (iii) नियम 17 के तहत स्व-विनियमन निकाय के निर्णय से उत्पन्न होने वाली अंतर विभागीय समिति की शिकायत या शिकायतों का संदर्भ ले, या यदि निर्धारित समय के भीतर स्व-नियामक निकाय द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है या कार्यक्रम संहिता या विज्ञापन संहिता के उल्लंघन से संबंधित ऐसी अन्य शिकायतें या संदर्भ प्राप्त होने पर, जैसाकि वह आवश्यक समझे,
- (iv) ब्रॉडकास्टर्स को उचित मार्गदर्शन और सलाह जारी करना
- (v) कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता के रखरखाव और पालन के लिए प्रसारकों को उचित आदेश और निर्देश जारी करना
- (vi) इसके आदेशों या निर्देशों और स्व-नियामक निकाय के गैर-अनुपालन के लिए कार्रवाई करना।

20. अंतर-विभागीय समिति

- (1) केंद्र सरकार सूचना और प्रसारण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में एक अंतर-विभागीय समिति का गठन करेगी, और इसमें महिला व बाल विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि और केंद्र सरकार के विशेषज्ञों सहित ऐसे अन्य मंत्रालयों और संगठनों के प्रतिनिधि, जिसमें विशेषज्ञ भी शामिल हैं, जैसाकि केंद्र सरकार निर्णय ले सकती है।
- (2) अंतर-विभागीय समिति शिकायतों या शिकायतों की सुनवाई के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया तैयार करेगी।
- (3) समिति समय-समय पर बैठक करेगी और कार्यक्रम संहिता व विज्ञापन संहिता के उल्लंघन या उल्लंघन के संबंध में शिकायतों की सुनवाई करेगी, जो

CATV GUIDELINES

- (i) arise out of appeal against the decisions taken at the Level I or Level II, as the case may be, or where no such decision is taken within the specified time;
 - (ii) be referred to it by the Central Government
- (4) The Inter-Departmental Committee shall examine complaints or grievances received by it and make any of the following recommendations to the Central Government, namely: -
- (i) advising, warning, censuring, admonishing or reprimanding such broadcaster; or
 - (ii) requiring an apology of such broadcaster; or
 - (iii) requiring such broadcaster to include a warning card or a disclaimer; or
 - (iv) requiring such broadcaster to delete or modify content or take the channel or a programme off-air for a specified time period where it is satisfied that such action is warranted, for reasons to be recorded in writing.
- (5) The Central Government may, after taking into consideration the recommendations of the Committee, issue appropriate orders and directions under sub-section (3) of section 20 of the Act for compliance by the broadcaster.



DISCLOSURE OF INFORMATION

- (1) A self-regulating body and a broadcaster shall make true and full disclosure of all grievances or complaints received by it, the manner in which the complaints are disposed of, the action taken on such complaints, the reply sent to the complainant, the orders or directions received by it and action taken on such orders or directions.
- (2) The information referred to in sub-section (1) shall be placed in public domain, and updated quarterly.
- (3) Subject to any law for the time being in force, the broadcaster shall preserve record of the content telecast by it for a minimum period of ninety days and make it available to the self-regulating body or the Central Government, or any other Central Government agency as may be requisitioned by it. ■

- (i) स्तर 1 या स्तर 11 पर लिये गये निर्णयों के खिलाफ अपील से उत्पन्न होता है, जैसा भी मामला हो, या जहां निर्दिष्ट समय के भीतर ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया जाता है
 - (ii) इसे केंद्र सरकार द्वारा संदर्भित किया जाए।
- (4) अंतर-विभागीय समिति उसके द्वारा प्राप्त शिकायतों या शिकायतों की जांच करेगी और केंद्र सरकार को निम्नलिखित में से कोई भी सिफारिश करेगी, अर्थात्
- (i) ऐसे प्रसारकों को सलाह देना, चेतावनी देना, निंदा करना, दंडित करना या फटकार लगाना या
 - (ii) ऐसे प्रसारक से माफी की अपेक्षा करना या
 - (iii) ऐसे प्रसारक से चेतावनी कार्ड या अस्वीकरण शामिल करने की अपेक्षा करना, या
 - (iv) ऐसे प्रसारक से सामग्री को हटाने या संशोधित करने या चैनल या किसी कार्यक्रम को निर्दिष्ट समय अवधि के लिए ऑफ एयर करने की आवश्यकता होती है, जहां यह संतुष्ट होता है कि लिखित रूप से दर्ज किये जाने वाले कारणों के लिए ऐसी कार्रवाई जरूरी है।
- (5) केंद्र सरकार, समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, प्रसारक द्वारा अनुपालन के लिए अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (3) के तहत उचित आदेश और निर्देश जारी कर सकता है।

सूचना का प्रकटीकरण

- (1) एक स्व-विनियमन निकाय और एक प्रसारक उसके द्वारा प्राप्त सभी शिकायतों या शिकायतों का सही और पूर्ण प्रकटीकरण करेगा, जिस तरीके की शिकायतों का निपटारा किया जाता है, ऐसी शिकायतों पर की गयी कार्रवाई, शिकायतों को भेजे गये उत्तर, इसके द्वारा प्राप्त आदेश या निर्देश और ऐसे आदेशों या निर्देशों पर की गयी कार्रवाई।
- (2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट जानकारी को सार्वजनिक डोमेन में रखा जायेगा और हर तीन महीने में अपडेट किया जायेगा।
- (3) कुछ समय के लिए लागू किसी भी कानून के अधीन, प्रसारक कम से कम 90 दिनों की अवधि के लिए उसके द्वारा प्रसारित सामग्री के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखेगा और इसे स्व-नियामक निकाय या केंद्र सरकार को उपलब्ध करायेगा या केंद्र सरकार की कोई अन्य एजेंसी जिसकी इसके द्वारा मांग की जा सकती है। ■